मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- ईएसआई अस्पतालों की हकीकत। 3
- विज की जासूसी कपूर की मायूसी
- अधिकारी चलवा रहे है मिलावट का धंधा 4
- सांप्रदायिकता जैसे गंभीर मसलों का हल
- अन्धविश्वास की खाद से बढ़ती बाबों की फ़सल 5
- मन की बात जुबां पर नहीं ही आयेगी!
- दिल्ली में केजरी का छाया-युद्ध 8
- कुंडली-गाज़ियाबाद-नौयडा-पलवल-बाईपास नौटंकी

वर्ष 28 अंक 19 फरीदाबाद, शनिवार, 1-15 अगस्त 2015 फोन : - 9999595632 2 ₹

हिन्दुत्ववादियों के दिलो-दिमाग में भरा जाता है कि उन्हें गंगा में मात्र एक डुबकी लगाकर अपने तमाम पापों को धोने की विशेष सुविधा प्राप्त है। वे सोचते हैं कि याकूब मेमन की एक फांसी को राष्ट्रवादी करार देने से भागलपुर कत्लोगारत, 1984 सिख कत्लेआम, हाशिमपुरा-मलियाना, शिवसेना प्रायोजित मुम्बई दंगे, कोडनानी, बजरंगी, मोदी के 2002 गुजरात, मुजफ्फरनगर जैसे बड़े-बड़े जन-संहारों में न्याय व्यवस्था की सारी जवाबदेही अपने आप समाप्त हो जायेगी।

हालाँकि आप मृत्युदंड के समर्थक हों या विरोधी इतना तो समझना होगा कि जब तक यह सजा कानून की किताबों में है अदालतें इसे देती रहेंगी। कौन इस सजा का पात्र है यह भी सम्बंधित अदालत तय करेगी। अदालत की नीयत पर बेशक सवाल न उठाया जाय पर निर्णय के सही-गलत की आलोचना का अधिकार लोकतंत्र में हर नागरिक के पास है। क्या याकूब मेमन की फांसी कायम रखनेवाले उसी सर्वोच्च न्यायालय के जिन जजों ने इसी मामले में दस अन्य की फांसी को आजीवन कारावास में बदला था वे बायस्ड कहलायेंगे ? मेमन की फांसी पर टिप्पणी करना भी अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता का दायरा हुआ न कि राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रद्रोह का।

याकूब मेमन को फ़ांसी ! और बाल ठाकरे को भारत रत्न ?

यह अब छिपा नहीं कि भाजपा की केन्द्र और महाराष्ट्र की सरकारों को याकूब मेमेन को फ़ांसी चढाने की जल्दी क्यों पड़ी है। आगामी बिहार चुनाव में मुंह बाये खड़ी हार से बचने के लिये भाजपा का एकमात्र सहारा हिन्दू ध्रुवीकरण है। उन्हें लगता है कि याकूब की फ़ांसी से हिन्दू-मुस्लिम विभाजन को वे अपने पक्ष में भुना सकेंगे। ऐसे किसी ध्रुवीकरण के तीखे होने का फ़ायदा एक और जो एजेंसी उठायेगी, वह है पाकिस्तान की खुफ़िया शैतान आईएसआई। मेमन की फ़ांसी उसे भी कितनी रास आयेगी यह गुरदासपुर थाने पर सीमा पार से आये आतंकियों के आत्मघाती हमले से स्पष्ट हो जाता है। एक ओर समूचे देश में इस फ़ांसी ने गंभीर बहस खड़ी कर दी है तो दूसरी ओर संघी प्रचारकों ने बहस करने वालों को देशद्रोही करार दिया है।

मज़दूर मोर्चा, दिल्ली ब्यूरो

हिन्दुत्ववादी देशभक्तों की सुनें तो हर वह व्यक्ति जो 1993 मुंबई बम-कांड के दोषी याकूब मेमन को बजाय फ़ांसी के आजीवन कारावास देने की बात करता है, वह स्वयं फ़ांसी का हकदार है। इस तर्क से तो उच्चतम न्यायालय के जज कुरियन जोसेफ़ को भी फ़ांसी दे देनी चाहिये जिन्होंने याकूब की फ़ांसी के खिलाफ़ अपील के निपटारे में दोष पाया और इस पर मुहर लगाने से इन्कार कर दिया। यहां तक कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में 11 फ़ांसी की सज़ा पाये दोषियों में से 10 की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। इस हिसाब से तो उन जजों को भी हिन्दुत्ववादी गिरोह देशद्रोही ही ठहरायेगा।

यह गिरोह किसी भी सीमा तक जाकर तर्कों को तोड़-मरोड़ सकता है। उदाहरण के लिये कोई भी व्यक्ति या समूह यह नहीं कह रहा कि याकूब मेमन दोषी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही उसे दोषी करार दे दिया तो भला कौन उसे निर्दोष कहेगा ? तार्किक समूहों की बात महज यहां तक सीमित है कि सुप्रीम कोर्ट को याकूब को बजाय फ़ांसी देने के आजीवन कारावास की सज़ा देनी चाहिये थी। पर हिन्दुत्ववादी गिरोह इस तर्क को अपने कुतर्क के जहर में डुबो कर इस तरह पेश कर रहा है मानो मेमन को बरी करने का अभियान चलाया जा रहा है।

सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर देश के नागरिकों को टीका टिप्पणी करने का अधिकार है या नहीं ? कानून का यह सर्वमान्य नियम है कि अदालती सुनवाई के दौरान अदालत के अन्तरिक निर्णयों पर टीका-टिप्पणी नहीं की जानी चाहिये। एक बार अन्तिम निर्णय आ जाय तो उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी की जा सकती है। यह हर किसी का संवैधानिक अधिकार भी है। जाहिर है हिन्दुत्ववादी गिरोह को भारतीय संविधान से कुछ लेना-देना नहीं। वे सिर्फ़ संघी विधान को जानते हैं जहां गुरू से असहमती नहीं व्यक्त की जा सकती।

याकूब मेमन को आजीवन कारावास देने के पक्ष में क्या तर्क है ? सबसे महत्वपूर्ण तर्क तो यह है कि मुंबई बम धमाकों के प्रमुख कर्ता-धर्ता, आईएसआई के निर्देशन में, दाऊद इब्राहीम और याकूब का बड़ा भाई टाइगर मेमन थे। वे सही अर्थों में फ़ांसी के हकदार हैं। यहां तक कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने उन 10 व्यक्तियों की फ़ांसी भी आजीवन कारावास में बदल दी जो घटनास्थल पर बम लगाने के दोषी पाये गये थे। न्यायालय का तर्क था कि ये सभी लोग कठपुतली थे और फ़ांसी की सज़ा मुख्य षड्यन्त्रकारियों को ही मिलनी चाहिये। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन को भी षड्यन्त्रकारियों में ही गिन लिया होगा, जिससे तमाम बुद्धिजीवी जिनमें भूतपूर्व जज भी शामिल हैं, इत्तफ़ाक नहीं रखते।

दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि याकूब मेमेन ने भारतीय मुप्तचर सेवा (रॉ) के समक्ष आत्मसमर्पण यह विश्वास दिलाने पर किया था उसे फ़ासी नहीं दी जायेगी। पर राजनीतिक आकाओं के निहित स्वार्थों के चलते यह तथ्य अदालती कार्यवाही का हिस्सा ही नहीं बनने दिया गया। विडम्बना यह है कि 1984 में सिख नरसंहार को उचित ठहराने वाले अमिताभ बच्चन, जिन्होंने उस वक्त 'खून का बदला खून' का नारा बुलंद किया था, को हिन्दुत्ववादी गिरोह परम देशभक्त मानता है। जबकि टाइगर मेमन को असली अपराधी बता कर उसके लिये फ़ांसी मांगने वाले सलमान खान को यही गिरोह देशद्रोही कहने से नहीं चूकता। सलमान का कसूर केवल इतना कि वह याकूब मेमन के लिये आजीवन कारावास सुझाने की हिमाकत कर बैठा। मज़ा यह कि यही हिमाकत भाजपा के अपने सांसद शत्रुधन सिन्हा ने भी की है पर वे इस गिरोह के निशाने पर नहीं है।

सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई बम धमाकों के एक माह पूर्व ही शहर में शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे की भड़काऊ अगुवाई में सैंकड़ों मुसलमानों को कत्ल किया गया था। इसकी जांच के लिये बनाये गये श्री कृष्ण आयोग ने बाल ठाकरे समेत कई हिन्दुत्ववादियों व पुलिस वालों को दोषी ठहराया था। पर उनके विरुद्ध कोई न्यायिक हलचल नहीं हो पाई। इसके ठीक पहले दिसम्बर 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के जिम्मेदार आडवाणी, ऊमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और तमाम अन्य हिन्दुत्ववादियों को भी आराम से मौज करते देखा जा सकता है। सवाल है कि देश में कानून का शासन सब पर एक जैसा है या मुंह देख कर टीका करने का ?

हिन्दुत्ववादी आजकल एक खुली धमकी का प्रयोग कर रहे हैं-जो भी उनके मुस्लिम विरोधी कुतर्कों से सहमत न हो, वह पाकिस्तान चला जाय। आसार यह बनते दिख रहे हैं कि अगर वे इसी तरह बेलगाम साम्प्रदायिक ज़हर उगलते रहे और दंगे-फ़साद प्रायोजित करते रहे तो हिन्दुस्तान के शहर-शहर में पाकिस्तान बनने की नींव पड़ जायेगी। यही ओवैसी जैसे मुसंघियों का भी एजेंडा है। आईएसआई का भी यही एजेंडा है। क्या हिन्दुत्ववादियों का भी यही छिपा एजेंडा है ?

सैकडों लोगों के हत्यारे मानवता के दो अपराधी फिर भी अपने अपने धर्म के कट्टरपंथियों के लिए सम्मानीय

याकूब मेमन

बाल ठाकरे

शासक वर्ग की कामयाब होती चाल, धर्मो के नाम पर बंटती आम जनता, जाति-धर्म के झगडे छोडो, सही लडाई से नाता जोडो।

ख़बर दार

किसके लिये ब्रांड एम्बैसेडर परणीति चोपड़ा

हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा अभिनेत्री परणीति चोपड़ा को 'बेटी बचाओ' का ब्रांड एम्बैसेडर घोसित करने से भाजपा के भीतर भी विवाद खड़ा हो गया है। अम्बाला कैन्ट, जहां से चोपड़ा आती हैं, के विधायक एवं सतत असन्तुष्ट मन्त्री अनिल विज ने जहां अपनी नाराजगी नहीं छिपाई वहीं महिला कल्याण मन्त्री कविता जैन ने बयान दे डाला कि परणीति को कभी ब्रांड एम्बैसेडर बनाया ही नहीं गया। क्योंकि बड़े धूम-धड़ाके के साथ खट्टर ने गुड़गांव में एक समारोह करके चोपड़ा को राज्य का ब्रांड एम्बैसेडर घोषित किया था; प्रस्तुत है इस मामले पर उनसे लिया गया एक काल्पनिक साक्षात्कार।

म.मो.-खट्टर साहब लोग जानना चाहते हैं कि परणीति चोपड़ा के ब्रांड एम्बैसेडर बनने से बेटी बचाओ का क्या ताल्लुक हो सकता है ?

खट्टर-आपने परणीति के विज्ञापन नहीं देखे ? वे कुरकुरे, नीविया, माज़ा, पैंटीन, वी चैट, स्पिंज़ और महिन्द्रा स्कूटी का विज्ञापन करती हैं। इन तमाम चीज़ों को लड़कियां ही तो इस्तेमाल करती हैं। हो गया न सम्बन्ध।

म.मो.-ऐसी तो बहुत सी पैसा लेकर विज्ञापन करने वाली महिलायें मिल जायेंगी। फ़िर भला परणीति चोपड़ा को ही आपने क्यों चुना ?

खट्टर-अरे भई हमारे करनाल का सांसद भी तो अश्विनी चोपड़ा है। पूछो उसे हमने क्यों चुना ? आखिर उसके जैसे भी तो सैंकड़ों बिकाऊ मीडिया वाले मिलते हैं। जब एक चोपड़ा को चुन लिया तो एक और से क्या एतराज। वैसे भी आजकल अश्विनी चोपड़ा कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा है। मुझे सलाह दे रहा था कि बजाय मुख्यमंत्री विंडो खोलने के लोग़ों के बीच जाना शुरू करो। अब देखता हूं कि मेरी वाली चोपड़ा के मुकाबले यह चोपड़ा कितने दिन टिक पाता है। वैसे भी यह तो कभी भूले से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में आता नहीं, बस इसकी बीवी जहां-तहां भाषण देती घूमती रहती है। तो उसके मुकाबले मैंने सोचा परणीति चोपड़ा भारी पड़ेगी।

म.मो.-अनिल विज से तो पूछ लिया होता। कुछ भी हो आखिर उनके निर्वाचन क्षेत्र की रहने वाली है और उनको ठेस तो लगी ही है।

खट्टर-इसीलिये तो नहीं पूछा। विज कभी मानता ही नहीं। उसके क्षेत्र में एक और सेलेब्रिटी सक्रिय हो जाय तो खतरा महसूस होना स्वाभाविक है। मैंने उसकी सुरक्षा के लिये सीआईडी लगाई थी पर उसने तो उस पर भी बवाल खड़ा कर दिया। विज जैसों से तो परणीति चोपड़ा ही बेहतर है। आई, मुस्कराई और गयी। न सीआईडी लगाने की जरूरत और न अपनी कुर्सी को कोई खतरा।

म.मो.-मतलब आपने एक तीर से दो शिकार किये। अश्विनी चोपड़ा को भी उसकी जगह दिखा दी और अनिल विज के भी पर कुतर दिये।

खट्टर-क्या करें, अब सत्ता-राजनीति में आ ही गया हूं तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहले अकेला विज ही बोलता था। अब वह अश्विनी चोपड़ा भी बोलने लगा जो अखबार में अपने सम्पादकीय भी भाड़े के लेखकों से लिखवाता है। इन पंजाबियों को कोई न कोई पंजाबी तड़का तो लगाना ही था।

म.मो.-खट्टर जी अन्त में यह तो बता दो कि हरियाणा की बेटियों को बचाने में परणीति चोपड़ा से क्या मदद मिलेगी ?

खट्टर-जो हरियाणा के मर्द परणीति चोपड़ा की फ़िल्में देखने में लगे रहेंगे तो उनके पास बेटियों को मारने का वक्त ही कहां बचेगा ? इसी लिये हमने परणीति चोपड़ा को हरियाणा में आने से छूट दे रखी है। बस खूब फ़िल्में बनाये जा। तेरी भी कमाई और मेरी भी मलाई। रही बात बेटियों की तो उसके लिये मोदी जी ने सेल्फ़ी वाला फार्मूला दे रखा है। सेल्फ़ी खींचे जाओ का मन्त्र अब तो हरियाणा की खापों ने भी पकड़ लिया है। बहुत हुआ तो कभी परणीति चोपड़ा की खाप वालों के साथ भी सेल्फ़ी करा देंगे।

छोटे देशों पर एहसान यानी यारों का कल्याण

जब भारत में अपनी खस्ताहाली है तो प्रधानमंत्री जनाब नरेन्द्र मोदी तमाम छोटे-छोटे देशों में जाकर सैंकड़ों करोड़ डॉलर के कर्जे और अनुदान क्यों बांटते फ़िर रहे हैं ? इन तमाम दौरों में क्यों ऐसे समझौतों के दौरान मोदी के बगल में प्राय: गौतम अडाणी को देखा जाता है ?

यह जानने के लिये किसी को बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय विशलेशक होने की जरूरत नहीं है। मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, मंगोलिया, श्रीलंका, मध्य एशिया के देशों में यात्राओं के दौरान ऐसे प्रोजेक्टस के लिये मोदी ने कर्ज/अनुदान दिये हैं जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अडाणी और अम्बानी जैसे उनके विश्वासपात्र चेले ही पूरा करेंगे। यानी एक हाथ से रकम उन देशों को दी जा रही है और दूसरे हाथ से वही रकम अपने यारों की तिजोरी में पहुंचाई जा रही है। यानी छोटे देशों पर एहसान भी हो गया और यारों का कल्याण भी। आस्ट्रेलिया के दौरे में तो हद ही हो गयी। वहां अडाणी को आस्ट्रेलियाई कोयला खानों के ठेके दिलाये गये और साथ गयी स्टेट बैंक ऑफ़ इन्डिया की अध्यक्ष से वहीं के वहीं 6000 करोड़ का कर्ज भी उसे दिला दिया गया। यानी भारतीय जनता की जमा-पूंजी से प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के दिनों से चल रहे पूंजीशाह दोस्त गौतम अडाणी को वहां की लूट में भागीदारी का लाइसेंस दिलाया गया। जाहिर है ऐसे लाइसेंस एकतरफ़ा तो हुआ नहीं करते। लिहाज़ा, आस्ट्रेलिया के पूंजीशाहों को भारत में निवेश कर लूटने की सुविधा दी गयी।

शासन का एक साल पूरा होते न होते मोदी के तमाम मन्त्रियों व मुख्यमंत्रियों के देशी घोटाले सामने आने लगे हैं। ये विदेशी घोटाले भी देर-सबेर बाहर निकलने ही हैं।